

विश्व शांति की बात

नरेन्द्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि शांति का मतलब युद्ध न होना नहीं है। यह ऐसा सूत्र वाक्य है, जिस पर गहराई से विचार करने, बहस करने और उसके सही अर्थ को समझ कर उसके अनुसार काम करने की आवश्यकता है। दुनिया पर नजर दौड़ाइए और देखिए कि जहां युद्ध नहीं हो रहा है, वहां क्या शांति है? वस्तुतः शांति के लिए युद्ध न हो, किसी प्रकार का टकराव न हो यह आवश्यक है। इस तरह युद्ध या किसी तरह के संघर्ष में सैनिक अपना बलिदान देकर हमें शांति की ओर से अग्रसर करते हैं।

मोदी ने यह सही कहा कि जहां कर्हीं भी विश्व शांति की बात होगी, भारत का नाम और उसका योगदान सुनहरे अक्षरों में लिखा होगा। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने की 100वीं वर्षगांठ दुनिया मनाने जा रही है। उससे भारत का सीधे कोई लेना-देना नहीं था किंतु भारतीय सैनिकों ने उसमें भाग लिया। जिस मोर्चे पर रहे बहादूरी के साथ लड़े और अपना बलिदान दिया। उस समय हमारा देश गुलाम था, और चूंकि ब्रिटेन युद्ध में शामिल था, इसलिए भारतीय सैनिकों को भी उसमें शिरकत करनी पड़ी। हम उनके बलिदान को नहीं भूल सकते। यह अच्छी बात है कि मोदी ने अपने कार्यकाल में शहीद हुए हर भूले-बिसरे जवानों को याद किया और उन्हें प्रदानजलि दी है। हमारे जवानों ने दुनिया को दिखाया है कि अगर युद्ध की बात आती है, तो वे किसी से पीछे नहीं हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में अदम्य साहस दिखाने के पीछे एक ही उद्देश्य रहा है, शांति बहाल करना। हमारे संस्कार में ही शांति है किंतु शांति केवल युद्ध होने और खत्म होने तक सीमित नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कि गरीबों में सबसे गरीब का विकास ही शांति का असल सूचक है। वास्तव में जब तक समाज में एक बड़ा तबका तंगहाली में जी रहा है, और विकास का लाभ उस तक नहीं पहुंच रहा तब तक समाज में शांति हो ही नहीं सकती। अगर बड़ा समूह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही तनाव में जी रहा है, तो शांति हुई कहां। किसी भी व्यवस्था का मूल यही होना चाहिए कि समाज के निचले पापदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए कितना काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सबको मिलाकर शांति का लक्ष्य हासिल करने का संदेश दिया है। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक इन समस्याओं के समाधान के लिए शासन और समाज एकजुट नहीं होता।

संवैधानिक संकट

श्रीलंका में जारी संवैधानिक संकट किस करवट बैठेगा, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन भारत के लिए निश्चित ही चिंता का विषय है। नेपाल, मालदीव और श्रीलंका की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि नई दिल्ली को पड़ोसी देशों के साथ इश्ते की नये सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है। हालांकि भारत ने श्रीलंका के संवैधानिक तखापलट पर संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि हम अपने घनिष्ठ पड़ोसी और लोकतांत्रिक देश श्रीलंका की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, और उम्मीद है कि वहां लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान किया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नवनियुक्त प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को बधाईदेकर राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना की अलोकतांत्रिक कार्रवाई को वैधानिकता देने की कोशिश की है। महिंदा राजपक्षे दो हजार चौदह में श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। उस दौरान उन्होंने चीन को अपने देश में निवेश करने के लिए पूरी तरह से छूट दे रखी थी। हालांकि श्रीलंका अब इसका खमियाजा भी भुगत रहा है। श्रीलंका में भारत की भी अनेक ढांचागत और आवासीय परियोजनाएं चल रही हैं। दरअसल, चीन दक्षिण एशियाई देशों में जरूरत से ज्यादा सक्रिय है, और उसकी सक्रियता भारत के लिए चिंता की बात है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत महसूस करता है कि उसके पड़ोसी देशों में मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं हों। इसलिए नई दिल्ली श्रीलंका के संवैधानिक संकट के मद्देनजर लोकतांत्रिक मान्यताओं

का सम्मान करने की बात कह रहा है।
 गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को राष्ट्रपति सिरीसेना ने रानिल विक्रमसिंधे को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। उनके फैसले की वहां के सर्विधान विशेषज्ञ, राजनीतिक नेता और मीडिया जमकर आलोचना कर रहे हैं। सिरीसेना ने विक्रमसिंधे को संसद में बहुमत साबित करने का मौका भी नहीं दिया जो पूरी तरह से गैर-लोकतांत्रिक है। हालांकि संसद के स्पीकर कारु जयसूर्य ने सिरीसेना के फैसले को खारिज करते हुए विक्रमसिंधे को प्रधानमंत्री के रूप में मान्यता दी है। अब सिरीसेना क्या जवाबी कार्रवाई करते हैं, देखा जाना है।

सत्संग

आशीर्वाद

करीब जब भी मेरे पास पहुंच जाता है तभी मैं अपने को असहाय पाता हूँ; क्योंकि मैं जो कर सकता हूँ, वह उसकी मांग नहीं है। गरीब आदमी कहता है कि मुझे नौकरी नहीं है। वह ध्यान की बात ही नहीं पूछता। उसको प्रार्थना से कुछ लेना-देना नहीं है। मेरा आशीर्वाद चाहता है कि नौकरी मिल जाए। मेरे आशीर्वाद से यह होता तो मैं एक दफ़ा में सभी को आशीर्वाद दे देता। मेरे आशीर्वाद से कुछ मिल सकता है, लेकिन वह नौकरी नहीं है। वह तुम्हारी मांग नहीं है। जब भी गरीब आदमी आता है तो मैं पाता हूँ कि उसकी कोई चिंतना धार्मिक है ही नहीं। कभी-कभी कोई धनी आदमी आता है तो उसकी चिंतना धार्मिक होती है। वह भी कभी-कभी। तब वह कभी पूछता है कि मन अशांत है, क्या करूँ? गरीब आदमी पूछता ही नहीं कि मन अशांत है। मन का अशांत होना एक खास विकास के बाद होता है। अभी पेट अशांत है; अभी मन को अशांत होने का उपाय भी नहीं है। पेट भर जाए तो मन अशांत होगा। मन भर जाए तो आत्मा बेचैन होगी। असल में, जब आत्मा बेचैन हो तभी मेरे पास आने का कोई अर्थ है। आत्मा बेचैन हो तो मेरे आशीर्वाद से कुछ हो सकता है, मेरे निकट होने से कुछ हो सकता है। जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वह धन और है। जो धन तुम मांगते हो, वह मेरे पास नहीं। गरीब कहते हैं अक्सर कि क्या रखा धन में! मगर यह सांत्वना है। यह वही हालत है जो लोमड़ी ने अंगूर की तरफ छलांग मार कर अनुभव की थी। अंगूर तक नहीं पहुंच सकी, फसला बड़ा था। एक खरगोश झांक रहा था। उस खरगोश ने कहा, क्यों मौसी, क्या मामला है? उस लोमड़ी ने कहा, मामला कुछ नहीं; अंगूर खट्टे हैं। छलांग छोटी है, इसे कहने में तो अहंकार को चोट लगती है। अंगूर खट्टे हैं, छलांग की जरूरत ही नहीं; बेकार सोच कर छोड़ दिए हैं। बहुत से गरीब आदमी कहते मिलते हैं: क्या रखा धन में! क्या रखा महलां में! क्या रखा पद्मों में! इससे यह मत समझ लेना कि समझ आ गई है। यह तो सिर्फ सांत्वना है। गरीब आदमी की छलांग छोटी है। मांग छोटी चीजों की है। अब मेरी तकलीफ तुम समझ सकते हो। तकलीफ यह है कि मैं उसे कुछ देना चाहूँ, जरूर देना चाहूँ; लेकिन जो मैं देना चाहता हूँ, वह उसके काम का नहीं है। जो वह मांगने आया है, वह न तो मेरे पास है, न देने योग्य है, न मांगने योग्य। लेकिन उसकी समझ तो उसे तभी आएगी जब वह गुजर जाए जीवन के अनुभव से।

बाइक रैली पर रोक

लोकतंत्र में कार्यक्रमों का अर्थ माना जाता है कि किसी संगठन के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम अपने विरोध, उत्साह, खुशी को कैसे प्रदर्शित करें, यह एक सामाजिक उत्पादन है। ऐसा कोई भी सामाजिक उत्पादन नहीं है जो किसी खास विषय तक सिमट कर रह जाता है। देर सबेर उसका विस्तार विभिन्न विषयों के साथ दिखाई देता है। मसलन, बाइक रैली राजनीतिक कार्यक्रमों का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि धार्मिक कार्यक्रमों का भी हिस्सा हो गई है। यदि हम कहें कि पिछले बीसेक सालों में विरोध, उत्साह और उन्माद को व्यक्त करने के एक मिले-जुले जिस तरीके का सबसे ज्यादा प्रसार हुआ है, वह बाइक रैली है। एक तरह से कहें कि राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के बीच अपने कार्यक्रमों के लिए इस बात की होड़ होती है।

राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के बीच अपने कार्यक्रमों के लिए इस बात का हँड़ हता है।

सतीश पेडणोकर

अपने विरोध, उत्साह, खुशी को कैसे प्रदर्शित करें, यह एक सामाजिक उत्पादन है। ऐसा कोई भी सामाजिक उत्पादन नहीं है जो किसी खास विषय तक सिमट कर रह जाता हो। देर सबेर उसका विस्तार विभिन्न विषयों के साथ दिखाई देता है। मसलन, बाइक रैली राजनीतिक कार्यक्रमों का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि धार्मिक कार्यक्रमों का भी हिस्सा हो गई है। यदि हम कहें कि पिछले बीसेक सालों में विरोध, उत्साह और उन्माद को व्यक्त करने के एक मिले-जुले जिस तरीके का सबसे ज्यादा प्रसार हुआ है, वह बाइक रैली है। एक तरह से कहें कि राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के बीच अपने कार्यक्रमों के लिए इस बात की होड होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा मोटरसायकिलें जुटाएं। इसका ही नतीजा था कि 15 फ़रवरी, 2018 को हरियाणा के जॉर्ड में भारतीय जनता पार्टी ने एक लाख मोटरसायकिल जुटाने का कार्यक्रम बनाया। इसके पीछे मक्सद बताया गया कि राज्य की राजनीति में नई हुंकार पैदा करने के लिए इतना बड़ा शक्ति का प्रदर्शन जरूरी है। शक्ति प्रदर्शन और लोकतंत्र में विभिन्न तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों को करने के बीच फर्क और उनके मक्सद अगल-अलग दिखने लगे हैं। लोकतंत्र में कार्यक्रमों का अर्थ माना जाता है कि किसी संगठन के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम अपने विरोध, उत्साह, खुशी को कैसे प्रदर्शित करें, यह एक सामाजिक उत्पादन है। ऐसा कोई भी सामाजिक उत्पादन नहीं है जो किसी खास विषय तक सिमट कर रह जाता हो। देर सबेर उसका विस्तार विभिन्न विषयों के साथ दिखाई देता है। मसलन, बाइक रैली राजनीतिक कार्यक्रमों का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि धार्मिक कार्यक्रमों का भी हिस्सा हो गई है। यदि हम कहें कि पिछले बीसेक सालों में विरोध, उत्साह और उन्माद को व्यक्त करने के एक मिले-जुले जिस तरीके का सबसे ज्यादा प्रसार हुआ है, वह बाइक रैली है। एक तरह से कहें कि राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के बीच अपने कार्यक्रमों के लिए इस बात की होड होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा मोटरसायकिलें जुटाएं। इसका ही नतीजा था कि 15 फ़रवरी, 2018 को हरियाणा के जॉर्ड में भारतीय जनता पार्टी ने एक लाख मोटरसायकिल जुटाने का कार्यक्रम बनाया। इसके पीछे मक्सद बताया गया कि राज्य की राजनीति में नई हुंकार पैदा करने के लिए इतना बड़ा शक्ति का प्रदर्शन जरूरी है। शक्ति प्रदर्शन और लोकतंत्र में विभिन्न तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों को करने के बीच फर्क और उनके मक्सद अगल-अलग दिखने लगे हैं। लोकतंत्र में कार्यक्रमों का अर्थ माना जाता है कि किसी संगठन के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों के जरिए अपनी कतार को और लंबी करने के मक्सद को पुरा करना चाहते हैं। लेकिन जब शक्ति प्रदर्शन का मक्सद हो तो स्पष्ट है कि वे या तो लोगों के सामने या सत्ता के सामने अपनी ताकत भर को जाहिर करना चाहते हैं। उस ताकत में जोड़ने की भावना के बजाय दबाने की प्रतिक्रिया होती है। पिछले कुछेक वर्षों में जिस तरह से बाइक रैलियों की तादाद बढ़ी है, उनमें लोकतंत्रिक मुल्यों के विस्तार से उल्ट शक्ति प्रदर्शन का मक्सद एक विचारधारा की तरह अपना विस्तार कर रहा है। हम इस पहलू पर विचार करें कि किसी भी तरह के प्रदर्शन और जुलूस में जो कुछ किया जाता है, उसकी गति लोगों के साथ जोड़ने के मक्सद किस हद तक जुड़ी रही है। लोगों के बीच से पैदल निकलना और उन्हें अपनी आवाज में शामिल करने की एक निश्चित गति होती है। बाइक की रफ़तार सड़कों के किनारे खड़े लोगों को छू भी नहीं सकती। बाइक की रफ़तार और उसका शोर संवाद की भी कोई गुंजाइश नहीं बनाता है। दरअसल, आवाज और शोर में यही फ़र्क है। इस पहलू पर हम कभी विचार नहीं करते कि राजनीतिक और समाज सुधार के लिए लोगों को संगठित करने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसका पर्यावरणीय उत्पाद किस तरह का है। वह वातावरण में भरोसे, वाली लय, ताल और धुन और ऊर्जा का निर्माण आक्रमकता का वातावरण तैयार कर रहा है। बाइक उत्पादित होने वाला जहरीला धुआं किस तरह से स्वयं घुलकर आम जिंदगी को मुश्किल बनाने में मददगार तरह के पर्यावरण को होने वाले नुकसान का आसाम सुधार और राजनीतिक हालात में बदलाव के बढ़ाने और राजनीतिक हालात में और कटुता पैदा करने की अभिव्यक्ति लगता है। ऊपर जिस रैली प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति लगता है। ऊपर जिस रैली प्रदुषण का एक पूरा ढांचा तैयार करते दिखाई देती है कि किसान ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर रैली के एक फ़सल कटवाने और तंग करने के आरोप लैली के एक आयोजक ने बताया कि मोटरसाइकिलों एक एंबुलेंस भी चलेगी ताकि आपात स्थिति में उसके सक्षमता की ताकत भर को जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन उसमें भी ज्यादा महान

चलते चलते

ਮੁਂਹਤੋਡ ਜਵਾਬ

क्रियता चाहिए। सीबीआई अस्थाना, वर्मा, सीबीआई शर्मा, सीबीआई सीबीआई इनते प्रकार की हो सकती हैं जैसे अब पता लगा। पर सीबीआई का वैसा ना जाए जैसा तमाम राजनीतिक हुआ है। कांग्रेस आई, कांग्रेस शरद, माजवादी वर्गहर।

टीशन हो जाएगा, निजी सेक्टर की फोन सर्विस ढंग से काम ना कर रही और चले जाओ। इस तरह का अहसास सुकून देता है। मेरे पास एक टेलीकॉम भी सर्विस थी, बहुत खराब। प्लि मैं गनी के पास चला गया, वह भी समान निकम्पी निकली। अब बीतराग-गाव आ गया है मेरे मन में। टेलीकॉम सीबीआई तक, सब जगह से संचार सपल्लाई हो, तब ही भारत विश्व गुरु बाय।

फोटोग्राफी



गुवाहाटी में
ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे
कचरा बीनती एक

प्रदृष्टि की समस्या

प्रदूषण की समस्या दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरह धुंध और धुएं के रूप में फैली है, जिसे स्पोग के नाम से जाना जा रहा है, वह अनायास नहीं है। इसका उचित समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में यह और खतरनाक रूप ले सकती है। दरअसल, इसका सबसे बड़ा और खतरनाक कारण पराली को खेतों में जलाना और उससे निकलने वाला धुआं है। जहां भी धान की खेती हो रही है, वहां यह एक विकट समस्या का रूप ले रहा है। चिंता की बात यह है कि कैसे इससे निजात मिलेगी? सरकार और किसान, दोनों के स्तर पर इसका संयुक्त समाधान क्या हो सकता है? इस तरह के कई सवाल हैं, जो इससे और हमारे जीवन से भी जुड़े हैं। इस धुंध पर जैसा हो हल्ला हो रहा है, वह वास्तविक समस्या की जड़ में पहुंचने की बजाय बेमानी शोर है। राज्यों की तू-तू मैं-मैं और दोषारोपण से सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और गैर-जिम्मेदारी को समझा जा सकता है। क्या यह पूरा सच है कि शहरों में चलने वाले वाहनों और उनकी बेतहाशा बढ़ती संख्या ही जिम्मेदार है? जिसे लेकर दिल्ली सरकार पिछले वर्ष के नाटक को इस वर्ष भी दोहराना चाहती थी। असल में यह दिल्ली सरकार का नाटक और ढोंग है, जो उसका सरकारी स्वभाव बन गया है। किसी भी समस्या की गंभीरता को बिना समझे उस पर इक्वेंट करना, उसे उत्सवी रूप

देना एक तरह की नकारा मानसिकता है। दिल्ली वालों के लिए साफ हवा, साफ पानी और साफ वातावरण की महती जरूरत है, क्योंकि दिल्ली माननीयों का शहर है। अब समय ने संकेत दे दिया है कि माननीयों को भी दिल्ली के बाहर देखना होगा और समय रहते बाहर वालों के विषय में भी सोचना होगा। दिल्ली में अन्य जगहों की तरह खेती-किसानी नहीं होती, लेकिन जहां खेती होती है, वहां का धुआं दिल्ली के जीवन को दमघोटू बना रहा है। इसके दो कारण हैं। पहला, दिल्ली की सधनता; और दूसरा, सधन बसावट और पेंड-पौधों की कमी यह धुआं देर तक वातावरण में रु का रहता है। दिल्ली से सटे अन्य क्षेत्रों में धुआं ज्यादा देर नहीं टिकता क्योंकि वहां हवा साफ है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, पेड़-पौधे अधिक हैं, और तथा ग्रामीण आबादी की सधनता कम है, जबकि दिल्ली-एनसीआर की सधनता बनिस्थत कई गुनाअधिक है। खेती का अधिकांश काम मरीनों से हो रहा है। लिहाजा, पराली जैसे अनेक कृषि अपशिष्टों की जरूरत कम रह गई है। दूसरी ओर, किसान को दूसरी फसल के लिए खेत को जल्द से जल्द खाली करना होता है, इसलिए उसके सम्पन्न जलाने के सिवा कोई दूसरा आसान विकल्प नहीं होता। पहले पराली का उपयोग पशुओं के चारे के लिए होता था। कृषि मजदूरों की उपलब्धता अधिक थी, इसलिए यह बहुत आसान होता था। उद्योगों को चलाने के लिए जो कोयला उपयोग होता है, उसके खनन में कमी आएगी जिससे हमारी खनिज सम्पदा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। दूसरा, जो धन खदानों से कोयला निकालने में खर्च होता है, उसका उपयोग कृषि अपशिष्ट से कोयला बनाने में हो तो किसानों और खेतिहार मजदूरों को फायदा होगा। शहरों और औद्योगिक इकाइयों पर दिनोंदिन बढ़ता बोझ भी कम होगा। देख सकते हैं कि नारियल के अपशिष्ट से बनने वाले कोयला अफ्रीका और यूरोप में निर्यात होता है। धान की भूसी का कोई उपयोग नहीं होता था लेकिन अब उससे से तेल निकलता है। इस प्रकार पर्यावरण और कृषि के अनुकूल सरकार को ध्यान देना होगा तभी मुकम्मल समाधान निकल सकता है। बिना किसी व्यस्थित समाधान के इससे मुक्त होना लगभग असंभव है।

